© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 09 , Issue : 03 | July - September 2022

किसान की संस्थागत ऋण तक पहुँच एवं संबंधित समस्याओं का अध्ययन

किरण बैनीवाल

शोधर्थिनी , समाज शाश्त्र विभाग , मेरठ कॉलेज मेरठ

डॉ० अमरजीत सिंह मलिक

एसोसिएट प्रोफेसर , समाज शाश्त्र विभाग , मेरठ कॉलेज मेरठ

सार

भारत में, ज्यादातर किसान अपने कृषि व्यवसाय को बनाए रखने के लिए बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा पर निर्भर हैं। इन ऋण सुविधाओं से उन्हें आधुनिकीकरण और भंडारण इकाइयों के निर्माण के लिए कृषि उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी। किसानों को कृषि गतिविधियों के सभी चरणों में ऋण सुविधाओं की आवश्यकता होती है। भारत सरकार वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए सहायता प्रदान करती है और आसानी से ऋण प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करती है। फिर भी, किसानों को बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पेपर में किसानों को कृषि ऋण प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया गया है। इस पत्र में प्रयुक्त शोध डिजाइन सुविधा नमूना तकनीक थी। शोधकर्ता ने डेटा विश्लेषण के लिए संरचनात्मक समीकरण विश्लेषण का इस्तेमाल किया। परिणाम से पता चला कि बैंक द्वारा लिया गया प्रसंस्करण समय किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। इसने संकेत दिया कि ईएमआई, जमानत और संपार्श्विक, ब्याज दर और प्रलेखन के पुनर्भुगतान में कठिनाइयों का भी बैंकों से ऋण प्राप्त करने पर प्रभाव पड़ा।

कीवर्ड: कृषि, संस्थागत ऋण, पूर्वी भारत, छोटे और सीमांत किसान, महिला किसान, काश्तकार किसान

परिचय

ब्याज की किफ़ायती दरों पर किसानों द्वारा पर्याप्त संस्थागत ऋण तक पहुंच भारत में कई कारणों से विशेष महत्व रखती है। पहला, संस्थागत ऋण कृषक समुदाय को निजी साहूकारों के चंगुल से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो सूदखोर ब्याज दर वसूल करते हैं और शोषण करते हैं। दूसरा, भारत में छोटे और सीमांत किसानों के पास शायद ही कोई निवेश योग्य अधिशेष है और इसलिए, संस्थागत ऋण की अपर्याप्त आपूर्ति से इनपुट उपयोग के साथ-साथ कृषि में निवेश और परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता में वृद्धि होने की संभावना है। हाल के वर्षों में भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लेकिन पिछले कई अध्ययनों और रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि कृषि के लिए वितरित संस्थागत ऋण के लिए छोटे किसानों द्वारा व्यापक क्षेत्रीय असंतुलन और असमान पहुंच है। व्यास समिति ने लगभग एक दशक पहले बताया था कि कुल ऋण में न केवल कृषि ऋण का हिस्सा घट रहा है, बल्कि कृषि के लिए ऋण की गति भी धीमी हो रही है, विशेष रूप से सावधि ऋणों के लिए और क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है और छोटे का हिस्सा बढ़ रहा है। किसानों के ऋण वितरण में गिरावट आ रही है । पूर्वी भारत जो कृषि और आर्थिक रूप से अविकसित है, संस्थागत ऋण की अपर्याप्तता से सबसे अधिक पीड़ित प्रतीत होता है। यह लेख पूर्वी भारत के विशेष संदर्भ में भारत में कृषि के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानता की प्रकृति और सीमा का विश्लेषण करता है, जिसमें मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश। लेख द्वितीयक और प्राथमिक दोनों डेटा पर आधारित है। प्राथमिक डेटा के उद्देश्य के लिए, एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई और बिहार के पटना और सहरसा, पश्चिम बंगाल के बर्दवान और कूच बिहार और खुर्दा और रायगडा जिलों में 1,200 कृषि परिवारों के बीच प्रचारित किया गया। ओडिशा के। छह जिलों में से प्रत्येक के लगभग 200 किसानों का साक्षात्कार लिया गया। कुल नमूने में से 506 सीमांत किसान, 371 छोटे किसान, 212 अर्ध-मध्यम किसान, 79 मध्यम किसान और 32 बड़े किसान थे।

किसान साथ ही, 393 स्व-किसान सह काश्तकार थे और 125 शुद्ध काश्तकार थे जो कुल नमूनों का एक हिस्सा थे। कुल 1,200 नमूना कृषि परिवारों में से 1,087 पुरुष प्रधान और 113 महिला प्रधान परिवार थे। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है और कृषि उत्पादन बढ़ाने में ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्थागत स्रोतों से पर्याप्त, समय पर और कम लागत वाले ऋण की उपलब्धता और पहुंच विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य आदानों के साथ, स्थायी और लाभदायक कृषि प्रणाली स्थापित करने के लिए ऋण आवश्यक है। अधिकांश किसान छोटे उत्पादक हैं जो व्यापक रूप से भिन्न क्षमता वाले क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। अनुभव से पता चला है कि सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच ग्रामीण गरीबों की उत्पादकता, संपत्ति निर्माण, आय और खाद्य सुरक्षा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए सरकार की प्रमुख चिंता सभी किसान परिवारों को बैंकिंग के दायरे में लाना और पूर्ण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

कृषि ऋण नीति

भारत सरकार ने इसमें सुधार के लिए कई नीतिगत उपाय शुरू किए हैं

ऋण के संस्थागत स्रोतों तक किसानों की पहुंच। इन पर जोर छोटे और सीमांत किसानों और समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करने के लिए प्रगतिशील संस्थागतकरण पर नीतियां रही हैं ताकि वे कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने में सक्षम हो सकें। नीति ऋण योजना, क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों को अपनाने और उधार नीतियों और प्रक्रियाओं के युक्तिकरण के माध्यम से जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह को बढ़ाने पर जोर देती है। इन नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप ग्रामीण परिवारों के संस्थागत ऋण के हिस्से में वृद्धि हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 19 प्रतिशत है और लगभग दो तिहाई आबादी कृषि पर निर्भर है, 60 प्रतिशत कंपनियां कृषि पर आधारित हैं उत्पादन, भारतीय किसानों द्वारा राष्ट्रीय

आय का 50 प्रतिशत। ताकि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो। भारत कृषि उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में कृषि का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का है और उससे भी पहले दक्षिण भारत के कुछ स्थानों में। कृषि में किसान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक किसान कृषि में लगा हुआ व्यक्ति है, जो भोजन या कच्चे माल के लिए जीवित जीव पैदा करता है। एक किसान खेती की जमीन का मालिक हो सकता है या दूसरों के स्वामित्व वाली भूमि पर मजदूर के रूप में काम कर सकता है। किसान अपनी बचत का उपयोग कृषि भूमि के उत्पादन और विकास के लिए कर रहे हैं। लेकिन भारत में ज्यादातर किसान छोटे हैं; उनके पास आय के सीमित संसाधन हैं। यदि वे अपनी बचत का उपयोग कृषि उत्पाद और कृषि भूमि के विकास के लिए करते हैं, तो वे अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए संस्थागत कृषि ऋण भारतीय किसानों के विकास का एक महत्वपूर्ण तरीका है। उपयोग में आसानी

संस्थागत कृषि ऋण

संस्थागत- एक बड़े संगठन से संबंधित जहां लोगों की देखभाल की जाती है या धारण किया जाता है। कृषि-इसमें सभी शाखाओं में खेती शामिल है और अन्य बातों के अलावा, मिट्टी की खेती और जुताई, उत्पादन, किसी भी कृषि और बागवानी वस्तुओं की खेती और कटाई, पशुधन को बढ़ाना शामिल है।

क्रेडिट- शब्द लैटिन शब्द क्रेडो से लिया गया है, जिसका अर्थ है "आई बिलीव"। क्रेडिट वह ट्रस्ट है जो किसी को अनुमति देता है पार्टी किसी अन्य पार्टी को धन या संसाधन प्रदान करने के लिए जहां दूसरी पार्टी पहले पक्ष को तुरंत प्रतिपूर्ति नहीं करती है, लेकिन बाद की तारीख में उन संसाधनों को चुकाने या वापस करने का वादा करती है। संस्थागत कृषि ऋण- इसका अर्थ है किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थान, मनी लैंडर्स, कमीशन एजेंट, व्यापारियों और जमींदारों द्वारा पौधों, फसलों और फसलों की कटाई के लिए ऋण प्रदान करना।

संस्थागत कृषि ऋण के स्रोत

1. संस्थागत ऋण

(ए) सहकारी ऋण समितियां- ग्रामीण ऋण का सबसे सस्ता और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। जब पहली बार सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी, तो यह सोचा गया था कि वे कई छोटे और मध्यम किसानों की लगभग संपूर्ण ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगी। नतीजतन, साहूकार पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं हुआ है। 1950-51 तक उन्होंने ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में निष्क्रिय भूमिका निभाई। हालाँकि, योजना अवधि के दौरान सहकारी समितियों ने लगातार प्रगति की है और कुछ हद तक सफल भी हुई हैं

किसानों के बीच मितव्ययिता और स्वयं सहायता को बढ़ावा देने में।

(बी) भूमि विकास बैंक (भूमि बंधक बैंक) -

मुख्य रूप से किसानों को 15 से 20 वर्षों की अवधि में कम ब्याज दरों पर अपनी भूमि के बंधक के खिलाफ दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। यदि महंगे भूमि सुधार कार्यक्रम (जैसे कुओं की खुदाई या गहरीकरण) किए जाने हैं, या यदि एकमुश्त खरीद के माध्यम से अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, या यदि पिछले ऋणों को चुकाना है, तो किसान ऐसे बैंकों से उधार लेना आकर्षक पाते हैं।

(सी) **वाणिज्यिक बैंक**- जून 1969 में शीर्ष 14 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले, उनके पास शहरी पूर्वाग्रह था। वे मुख्य रूप से शहरी लोगों से जमा स्वीकार कर रहे थे और व्यापार और उद्योग को ऋण दे रहे थे। उनके द्वारा कृषि और ग्रामीण उद्योगों की उपेक्षा की गई। चूंकि कृषि अपने स्वभाव से एक जोखिम भरा उद्यम था, निजी वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों से दूर हो गए थे, 1969 में वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से ग्रामीण ऋण की संस्थागत संरचना के विस्तार और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। हालाँकि, आज भी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संस्थानों द्वारा ठीक से सेवा नहीं दी जाती है।

(डी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 1975 में, सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों और सामान्य रूप से ग्रामीण गरीबों की विशेष जरूरतों को देखने के लिए

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक नेटवर्क स्थापित किया। सितंबर 1990 से संचालित 196 आरआरबी की अनूठी विशेषता यह है कि वे भारत में फैली लगभग 14,800 शाखाओं के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों को पूरा करते हैं। लगभग सभी आदिवासी जिलों को कवर किया गया है। आरआरबी लगभग रु। प्रति वर्ष औसतन 400।

(e)सरकार- ने आपात स्थिति में किसानों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान किया है जैसे

बाढ़ या अकाल। ऐसे ऋणों को तकावी ऋण के रूप में जाना जाता है। ऐसे ऋण रियायती ब्याज दर (6%) पर दिए जाते हैं और पुनर्भुगतान का तरीका भी बहुत सुविधाजनक होता है। भूमि कर के भुगतान के समय इसे कई किश्तों में चुकाया जा सकता है।

साहित्य की समीक्षा

(दक्षिणा और राजेंद्रन 2018) ने "कृषि ऋण सुविधाओं तक किसानों की पहुंच पर चुनौतियां और समस्याएं" का अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि और भारत में, ज्यादातर किसान बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा पर निर्भर हैं। अपने कृषि व्यवसाय को बनाए रखने के लिए। इन ऋण सुविधाओं से उन्हें आधुनिकीकरण और भंडारण इकाइयों के निर्माण के लिए कृषि उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी। किसानों को कृषि गतिविधियों के सभी चरणों में ऋण सुविधाओं की आवश्यकता होती है। भारत सरकार वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए सहायता प्रदान करती है और आसानी से ऋण प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करती है। फिर भी, किसानों को बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पेपर में किसानों को कृषि ऋण प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया गया है।

(हक और गोयल 2021) ने "पूर्वी भारत में किसानों द्वारा संस्थागत ऋण तक पहुंच" का अध्ययन किया और पाया कि संस्थागत ऋण की आपूर्ति कृषि विकास को बढ़ावा देने और किसानों को निजी साहूकारों के चंगुल से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो अत्यधिक

उच्च दर वसूलते हैं। ब्याज की और उन्हें सदा के कर्ज के जाल में जीने के लिए मजबूर करते हैं। हाल के वर्षों में कृषि के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है लेकिन यह क्षेत्रों के बीच काफी असमान रहा है। 2018-2019 तक, दक्षिणी क्षेत्र का संस्थागत ऋण में सबसे अधिक हिस्सा (43.0%) था, उसके बाद उत्तरी क्षेत्र (21.0%), मध्य क्षेत्र (13.6%), पश्चिमी क्षेत्र (12.0%), पूर्वी क्षेत्र (9.0%) का स्थान था। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (0.9%) क्रमशः। पूर्वी भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता के बारे में इतनी चर्चा के बावजूद, लगभग सभी पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के लिए संस्थागत ऋण बहुत खराब रहा है। ऋण-जमा अनुपात, ऋण अवशोषण क्षमता, कृषि विविधीकरण के स्तर और उच्च कृषि विकास और गरीबी में कमी के लिए अप्रयुक्त क्षमता जैसे विभिन्न मानक मानदंडों के आधार पर, पूर्वी राज्यों के किसान संस्थागत ऋण तक पहुंच के मामले में बेहतर सौदे के पात्र हैं। इसके अलावा, लेख पूर्वी भारत में किसानों के कम ऋण अवशोषण के मिथक को उजागर करता है।

(मार्टिनेज 2013) ने "कृषि ऋण तक किसानों की पहुंच" का अध्ययन किया और पाया कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है और कृषि उत्पादन बढ़ाने में ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्थागत स्रोतों से पर्याप्त, समय पर और कम लागत वाले ऋण की उपलब्धता और पहुंच विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य आदानों के साथ, स्थायी और लाभदायक कृषि प्रणाली स्थापित करने के लिए ऋण आवश्यक है। अधिकांश किसान छोटे उत्पादक हैं जो व्यापक रूप से भिन्न क्षमता वाले क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। अनुभव से पता चला है कि सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच ग्रामीण गरीबों की उत्पादकता, संपत्ति निर्माण, आय और खाद्य सुरक्षा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए सरकार की प्रमुख चिंता सभी किसान परिवारों को बैंकिंग के दायरे में लाना और पूर्ण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

(शोभा और सिजी 2018) ने "विशेष संदर्भ के साथ कृषि ऋण तक पहुंचने में किसानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं" का अध्ययन किया और पाया कि कृषि क्षेत्र के लिए कृषि

ऋण एक विकासशील रणनीति बना हुआ है। भारत। वर्तमान अध्ययन में मालूर तालुक के किसानों की ऋण संबंधी समस्याओं और उनके संभावित परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे पता चलता है कि कृषक समुदाय की संस्थागत ऋण आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। स्तरीकरण के साथ गैर-संभाव्यता तीन चरणों के नमूने को अपनाया गया था। पहले चरण में स्तर का चयन किया गया था यानी मलूर क्षेत्र का चयन किया गया था। दूसरे चरण में, उत्पादन स्तर के आधार पर मलूर में पांच गांवों अर्थात् अग्रहारा, कांबीपुरा, कोडुरु, बेल्लावी और अर्लेरी का चयन किया गया था। तीसरे चरण में साधारण यादृच्छिक न्यादर्श के आधार पर लगभग 500 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। प्रत्येक गांव से लगभग 25 सीमांत, लघु, मध्यम और बड़े किसानों का चयन किया गया। विश्लेषण में प्रयुक्त सांख्यिकीय तकनीकें प्रतिशत विधि, रैंकिंग और क्रुस्कल वालिस्टेस्ट हैं। अध्ययन से पता चला कि कृषि के लिए औपचारिक ऋण तेजी से बढ़ा और यह मलूर में किसानों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सका और उन्हें अपनी उत्पादक और अनुत्पादक जरूरतों के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए अनौपचारिक ऋण का सहारा लेना चाहिए।

निष्कर्ष

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है। लेकिन किसानों द्वारा कृषि क्षेत्र में अधिकतम लाभ प्राप्त करना आजकल एक बड़ा प्रश्न था। वर्तमान में, किसानों को पानी की कमी, इनपुट की उच्च लागत, विपणन मुद्दों और ऋण समस्याओं आदि जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादन, विपणन और अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए कृषि ऋण आवश्यक है। इसलिए सरकार को कुछ सब्सिडी और कम ब्याज दर के साथ अधिक क्रेडिट देकर किसानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। सरकार को और अधिक ऋण योजनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत उपयोगी होंगी.

संदर्भ

1. धक्षाना, आरती जे.डी., और के.वी.आर. राजंद्रन। 2018 "कृषि ऋण सुविधाओं तक किसानों की पहुंच में चुनौतियां और समस्याएं।" मानविकी और सामाजिक विज्ञान के सेंट थेरेसा जर्नल 4(1):50-62.

2. हक, टी., और अंकिता गोयल। 2021. "पूर्वी भारत में किसानों द्वारा संस्थागत ऋण तक पहुंच।" जर्नल ऑफ़ एशियन डेवलपमेंट रिसर्च

3. मार्टिनेज, एलआईसी। इग्नासियो गुज़मैन। 2013. "

4. शोभा, के., और के. सिजी। 2018 "किसानों को कृषि ऋण प्राप्त करने में विशेष संदर्भ 6(1):1398-1405 के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।